

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.



## राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बृहद्वार, 8 सितम्बर, 2004/17 भाइपद, 1926

### हिमाचल प्रदेश दसवीं विधान सभा

कार्यालय उपायुक्त, विलासपुर, जिला विनामार, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आंदेश

विलासपुर, 3 सितम्बर, 2004

संख्या वी० ए० ०००-०८-१६/७९-III-४०७३-८९.—योकि श्रीमती लरस्वती देवी, निवासी गाँव खाल, डा० सलोआ, जिला विलासपुर, जो विकास खण्ड नदर की ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं०-४ से पंच के पद पर निर्वाचित घोषित हुई थी, ने घरेलू परिव्यवस्थाओं के कारण दिनांक 4-3-2004 से ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं०-४ से पंच पद से त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, नदर के पद मंड्या 435, दिनांक 19-5-2004 के अन्तर्गत की गई तथा वह त्याग-पत्र, जिला पंचायत अधिकारी, विलासपुर द्वारा अधिसूचना मंड्या 3916-22, दिनांक 10-8-2004 के अन्तर्गत स्वीकृत करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड पंच का पद दिनांक 4-3-2004 से रिक्त हो गया है।

इतः गैं, सुभाषीण पांडा (धा० प० से०) उपायुक्त विनासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) तथा (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जिना के विकास खण्ड सदर की ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं०-४ के गंव का पद दिनांक 4-3-2004 से विक्त घोषित रहता है।

गुभाषीण पांडा,  
उपायुक्त,  
जिला विनासपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय उत्तापुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कारण लताश्रो नोटिस

धर्मशाला, 31 अगस्त 2004

सं० ८० सी० ए० न०-के० जी० आर०-ई० (९) ३८/२००१-४३८०-८४.—“गैं सुभिया राण, पंचायत गदस्य, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरिया ने शिकायत की थी कि श्री गुरुन कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़ ने शरकारी भूमि स्थित खसरा नं० १८८५/२ व खसरा नं० १८०६, रक्बा ८-०१-४२ हैक्टेयर मौजा कुठेहड़ पर कांचा करके दुकानें बनाई हैं इस मामले की जांच उप-मण्डलाधिकारी (ना०), ज्वाली द्वारा तहसीलदार खालो के माध्यम से करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने आपने कार्यालय क्रम संख्या ७४६, दिनांक 25-०६-२००४ के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिसके अनुसार खसरा नं० १८०५/२ व खसरा नं० १८०६ रक्बा ८-०१-४२ हैक्टेयर मौजा कुठेहड़ पर सुशील कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के कब्जे की पुष्टि की गई है जिसके अतिरिक्त आपने उक्त खसरा नम्बरान पर तब्जे के नियमितिकरण के लिए शपथ-पत्र भी दायर किया है।

इतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (सी०) के अनुसार श्री सुशील कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरिया प्रधान पद पर बने रहने के श्रयोग्य हो चुके हैं।

प्रतः यात्रको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा, 131(1) के अन्तर्गत कारण दत्तात्रे नोटिस जारी किया जाता है कि कांगड़ा न उपरोक्त अधिनियम की धारा 122(1) (सी०) के अधीन आपको प्रधान पद ग्राम पंचायत कुठेहड़ के पद पर बने रहने के श्रयोग्य घोषित किया जाये, आपका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, नगरोटा सूरियों के माध्यम से १५ दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि यात्र आपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहते अपितु आपको आरोप स्त्रीकार है तथा मामले में एक तरफा कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

श्रीकान्त वाल्दी,  
उपायुक्त,  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SHIMLA DISTRICT, SHIMLA (H. P.)

### NOTIFICATION

Shimla-1, the 31st August, 2004

No. SML-Reader ADM (716) 94-5000-03.—Whereas the Director Transport, Himachal Pradesh Shimla has informed that the pre-paid taxi system is going to be started in Shimla

Town shortly. He has also suggested the places for parking of pre-paid taxis in Shimla town in order to start the said system;

And whereas, I am of the opinion that in the interest of public convenience and safety it is necessary to earmark/notify parking places in Shimla town to start the pre-paid taxi system.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in me under section 117 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with Rule 196 of the Motor Vehicles Rules, I, S. K. B. S. Negi, District Magistrate, Shimla hereby order that the following places in Shimla town shall be used as Parking places for pre-paid taxis:—

1. Bus Stand	3 Taxis
2. Victory Tunnel	2 -do-
3. Railway Station	3 -do-

These order shall come into force with immediate effect.

S. K. B. S. NEGI,  
District Magistrate, Shimla.

कार्यालय उपायुक्त, मोलन, जिला मोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मोलन, 26 जूलाई, 2004

मंज्या एस 0 एल 0 एन 0-XII-106 (पंच) /73-5110-17. —यह कि ग्राम पंचायत बखालग, की दिनांक 6-4-2004 की बैठक जो उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, की अध्यक्षता में मम्पन्न हुई, के प्रस्ताव मंज्या 2 में पारित किया गया था कि प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, श्री गीता राम, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की निम्ननिमित्त बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे पंचायत का कार्य प्रभावित हुआ है :—

1. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 8-3-2004
2. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26-3-2004
3. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 6-4-2004
4. ग्राम सभा की बैठक दिनांक 4-4-2004

प्रधान के उपरोक्त बैठक में अनुपस्थित रहने की पुष्टि खण्ड विकाम अधिकारी कुनिहार, द्वारा पंचायत रिकाई से करवाई गई और आरोप उनके रिपोर्ट अनुसार मही पाए गए थे।

इस सन्दर्भ में प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, को इस कार्यालय में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने वारे "कारण बताओ नोटिस" जारी किया गया था।

प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, से कारण बताओ नोटिस, का उत्तर इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उत्तर में प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, द्वारा ग्राम पंचायत बखालग की उपरोक्त बैठक दिनांक 8-3-2004 व 26-3-2004 के सम्बन्ध में अनुपस्थित रहने का कारण अपनी अस्वस्थना बताया है। जिसकी मौजिक सूचना उनके उत्तर अनुसार पंचायत सहायक को दे दी गई बतलाई है और दिनांक 4-4-2004 की ग्राम सभा

की बैठक के मम्बन्ध में भी प्रधान ने अपने जवाब में दर्शाया है कि हमकी मौखिक सूचना भी उप-प्रधान को दी गई थी।

परन्तु यह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ब) के अन्तिम पैरा में दिया गया है कि जहां पदाधिकारी ने पंचायत को खण्ड (ब) के अधीन अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन दिया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तरीख से एक मास के भीतर, आवेदन पर अपने विनियोग को आवेदक को मूचित करने में असफल रहती है, वहां पंचायत द्वारा अबकाण स्वीकृत किया गया समझा जाएगा :

परन्तु प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, के उपरोक्त वर्णन कारण बताएँनोटिस में उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग द्वारा ग्राम पंचायत को कोई आवेदन नहीं दिया गया था। वर्णोंके उनके उत्तर अनुसार उन्होंने केवल मान मौखिक सूचना दी गई बताई है, जोकि अधिनियम की उपरोक्त धारा 131 (1) (ब) की परिधि में नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बखालग, का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ब) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा० प्र० म०) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) में प्राप्त है, प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग का पद रिक्त घोषित करना हूं और श्री गीता राम को आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत बखालग, की कोई चल-प्रचल सम्पत्ति हो तो, उसे तत्काल मचिव, ग्राम पंचायत बखालग के पास जमा कर दें।

राजेश कुमार,  
उपायुक्त,  
सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०)।